

[2019] 13 एस.सी.आर.442

एम. हरिहरसुधन

बनाम

आर. कारमेगम एवं अन्य

(2019 की दीवानी अपील संख्या 8069)

17 अक्टूबर, 2019

[मोहन एम. शांतनागौडर एवं अजय रस्तोगी, न्यायमूर्तिगण]

तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992:

धारा 7, 10 और 14 - क्या अधिनियम दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित करता है - उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा यह माना कि हालांकि दीवानी क्षेत्राधिकार पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है, चूंकि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम संपत्ति के नुकसान के मुआवजे का दावा करने के लिए एक विशेष तरीका प्रदान करते हैं, इसलिए मुआवजे का दावा करने के अन्य सभी तरीके निहितार्थ वर्जित थे - उच्चतम न्यायालय में अपील - अभिनिर्धारित : अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा केवल एक अतिरिक्त उपाय की प्रकृति का है - अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ द्वारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बेदखल करता है - धारा 14 हर्जाने के वाद पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार को मान्यता देती है - तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992 - क्षेत्राधिकार।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : 1. विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बेदखली के प्रश्न का अनुमान तब तक सहजता से नहीं लगाया जाना चाहिए

जब तक कि नीचे दी गई शर्तें पूरी न हों। जहाँ कानून विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिमता प्रदान करता है, वहाँ व्यवहार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को तभी वर्जित माना जाना चाहिए यदि उन कार्यों को करने के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हों जो दीवानी न्यायालय सामान्यतः एक वाद में करते हैं। जहाँ कोई स्पष्ट अपवर्जन नहीं है, वहाँ विधायिका के मंतव्य का पता लगाने के लिए उपचारों और विशेष अधिनियम की योजना की जांच आवश्यक हो जाती है और इस जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। बाद वाले मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या कानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है और उस अधिकार या दायित्व के निर्धारण का प्रावधान करता है और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या व्यवहार न्यायालयों की कार्रवाइयों से सामान्य रूप से जुड़े उपचार उक्त कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं या नहीं। [कंडिका 6] [448-ड-ज; 449-ख-ग]

धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1968] 3 एस.सी.आर.

662 – अनुसरण किया गया।

2. इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि की रोकथाम) अधिनियम, जो 1992 में अधिनियमित किया गया था, प्रारंभ में केवल सार्वजनिक संपत्ति को हुई क्षति और हानि से संबंधित था। अधिनियम में तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (नुकसान और हानि की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1994 के माध्यम से संशोधन किया गया था, जिसे 09.08.1994 को तमिलनाडु सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, ताकि सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में भी मुआवजा प्रदान किया जा सके। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 09.04.1994 को लागू हुए, यानी अधिनियम के संशोधन से पहले। हालांकि नियमों में बाद में जी.ओ. एमएस संख्या 1285, गृह (न्यायालय IV) दिनांक 24.10.1994 के माध्यम से कुछ संशोधन किए गए थे,

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करने में चूक की है, और सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में नुकसान के दावे और मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान करने में विफल रही है। नियमों का समग्र रूप से केवल पठन ही यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार ने नियमों को संशोधित कानून के अनुरूप बनाने और उसके उचित प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए उचित रूप से संशोधित करने में चूक की है। [कंडिका 9] [453-ख-घ, छ]

3. भले ही यह मान लिया जाए कि नियम व्यापक रूप से सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों को हुई क्षति या हानि के लिए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं, अधिनियम की योजना दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बेदखली की परिकल्पना नहीं करती है। [कंडिका 10] [453-ज; 454-क]

4. नियमों को शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि विस्तृत रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम, नियमों के साथ मिलकर, दो तरीकों से मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान करता है। पहला, यह अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के मुकदमे के अंत में प्रदान किया जा सकता है, या आरोपी पर लगाए गए जुर्माने में से भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।

यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत मुआवजा देने की आपराधिक न्यायालय की शक्ति के समान है। दूसरा, नियमों के तहत परिकल्पित संक्षिप्त जांच के बाद, धारा 10 के तहत परिकल्पित आवेदन पर मुआवजा दिया जा सकता है। यह कुछ हद तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए परिकल्पित संक्षिप्त प्रक्रिया के समान है। यह इंगित करेगा कि अधिनियम और नियम संपत्ति के नुकसान और हानि के लिए मुआवजे का दावा करने हेतु एक विशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। [कंडिका 11]

5. यह स्पष्ट है कि धारा 7 स्पष्ट रूप से अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही के

बाद, उसी मामले से संबंधित एक दीवानी वाद की संभावना को मान्यता देती है, जहाँ यदि दीवानी वाद की सुनवाई करने वाला न्यायालय मुआवजा दे रहा है, तो उसे अधिनियम की धारा 7 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह तर्कसंगत नहीं है कि अधिनियम दीवानी न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार को वर्जित करते हुए बाद में दीवानी वाद दायर करने की अनुमति देगा। इसके अलावा, नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 के तहत परिकल्पित मुआवजा प्राप्त करने का संक्षिप्त उपाय भी हर्जाने के लिए वाद दायर करने से नहीं रोकता है। धारा 14 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यह अधिनियम उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त है, न कि उसके अल्पीकरण में। यह आगे यह भी अधिदेशित करता है कि अधिनियम में निहित कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को जांच या अन्य कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो अधिनियम के अलावा उसके विरुद्ध शुरू की जा सकती है। लागू "कानून" में सामान्य कानून शामिल होगा, जिसके तहत हर्जाने के अपकृत्यपूर्ण उपाय का दावा किया जा सकता है, और जिस उपाय को केवल दीवानी न्यायालय में ही अपनाया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, धारा 14 के माध्यम से, हर्जाने के वाद पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 भी इस अधिनियम की धारा 14 के समान है, जो यह प्रावधान करती है कि 1986 का अधिनियम लागू अन्य कानूनों के अतिरिक्त है न कि उनके अल्पीकरण में। [कंडिका 13 और 14]

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारत संघ [2019] 8 एस.सी.सी. 416 ; *कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी* (2003) 2 एस.सी.सी. 412 : [2003] 1 एस.सी.आर. 397; *इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी. पी. शांता* (1995) 6 एस.सी.सी. 651 : [1995] 5 पूरक. एस.सी.आर. 110 – पर भरोसा किया गया।

6. अधिनियम की धारा 14, लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अतिरिक्त होने और उनके अल्पीकरण में न होने के कारण, किसी पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 10 के तहत परिकल्पित उपाय का लाभ उठाने के बजाय, यदि वह चाहे तो राहत के लिए दीवानी न्यायालय जाने की अनुमति देती है। स्पष्ट रूप से, अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा केवल एक अतिरिक्त उपाय की प्रकृति का है जिसे उसी राहत के लिए दीवानी वाद दायर करने के स्थान पर अपनाया जा सकता है। [कंडिका 14]

7. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि चूंकि धारा 10 के तहत मुआवजे के दावे को केवल संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए यह उन उपायों के पूर्ण विकल्प के रूप में नहीं है जिन्हें दीवानी न्यायालय में अपनाया जा सकता है और एक पूर्ण परीक्षण के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, भले ही अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे का निर्धारण करने वाले निर्धारित प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हों। इस प्रकार, यह अधिनियम सामान्य कानून के तहत हर्जाने के दावे का स्थान नहीं लेता है और न ही उसे रोकता है जो दीवानी वाद में दीवानी न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए आ सकता है। अधिनियम न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ द्वारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बेदखल करता है। [कंडिका 15 और 16]

नज़ीर संदर्भ

1968 (3) एस.सी.आर.662	अनुसरण किया गया	कंडिका 4.2
[2019] 8 एस.सी.सी. 416	भरोसा किया गया	कंडिका 14.1
[2003] 1 एस.सी.आर. 397	भरोसा किया गया	कंडिका 14.1
[1995] 5 पूरक. एस.सी.आर. 110	भरोसा किया गया	कंडिका 14.2

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2019 की दीवानी अपील संख्या 8069.

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के अपील वाद (एम.डी.) सं. 143/2018 में दिनांक 29.03.2019 को दिए गए निर्णय और आदेश से।

वी. गिरि, वीरा काथिरवन, वरिष्ठ अधिवक्तागण; मुथु सरन, एम. पी. पार्थिवन, ए. एस. वैरावन, हार्दिक गौतम, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण।

जी. शिवबलमुरुगन, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

मोहन एम. शांतनगौडर, न्यायमूर्ति।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा अपील वाद (एम.डी.) संख्या 143/2018 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 29.03.2019 से उत्पन्न हुई है, जिसके माध्यम से 2016 की ओ.एस. 186 में असफल प्रतिवादियों (यहाँ उत्तरदाता) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर हर्जाने के वाद को प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मदुरै ने दिनांक 03.04.2018 के आदेश द्वारा डिक्री किया था।

3. इस अपील में संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (संक्षेप में "अधिनियम") के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा दायर हर्जाने का वाद विचारणीय है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह अधिनियम दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित करता है। इस संबंध में, अपीलकर्ता द्वारा आरोपित मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 अपीलकर्ता मदुरै में एक होटल चलाता है। उसने अपने पिता के स्वामित्व वाले

भूखंड के बगल में एक भूखंड खरीदा था, जहाँ उसने 2014 में निर्माण कार्य शुरू किया। अपीलकर्ता के पिता ने उत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध व्यादेश की राहत के लिए ओ.एस. संख्या 783/2014 दायर किया, क्योंकि उत्तरदाता संख्या 1 ने अपीलकर्ता के पिता की संपत्ति तक मुफ्त पहुँच को बाधित करते हुए अपीलकर्ता की संपत्ति के सामने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। हालाँकि उक्त वाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था, फिर भी उत्तरदाता संख्या 1 ने अपना निर्माण पूरा कर लिया। बाद में, वाद दायर किए जाने से क्षुब्ध होकर, उत्तरदाता संख्या 1 ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर अपीलकर्ता की संपत्ति पर कुछ निर्माण सामग्री को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 2.27 लाख रुपये का नुकसान हुआ। परिणामस्वरूप अपीलकर्ता ने पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई और उत्तरदाता संख्या 1 के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। उत्तरदाता संख्या 1 ने बाद में पत्थरबाजी करके अपीलकर्ता के होटल के शो-केस कांच को और अधिक नुकसान पहुँचाया और होटल में कार घुसाकर उसके स्वचालित कांच के दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया। उत्तरदाता संख्या 2 और 3 ने होटल में अनाधिकृत प्रवेश किया और 1 लाख रुपये से अधिक की नकदी ले गए। अपीलकर्ता ने अपने घायल कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च पर 73,000 रुपये खर्च किए, और बाद में ओ.एस. 186/2016 दायर किया।

3.2 विचारण न्यायालय ने वाद में डिक्री प्रदान करते हुए यानी 2016 की ओ.एस. संख्या 186, यह माना कि अपीलकर्ता 18,28,941/- रुपये के हर्जाने का हकदार था, जिस पर वाद दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 9% वार्षिक दर से ब्याज और आनुपातिक खर्च देय होगा। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद की विचारणीयता कोई मुद्दा नहीं थी।

3.3 उच्च न्यायालय ने, अपील में, वाद की विचारणीयता, आवश्यक पक्षों के गैर-संयोजन और वाद के कारण के उद्भव के संबंध में विचारार्थ बिंदु तैयार किए। हालाँकि यह

माना गया कि आवश्यक पक्षों के गैर-संयोजन के कारण वाद दोषपूर्ण नहीं था और न ही इसे समय से पहले दायर किया गया था, फिर भी डिक्री को पूरी तरह से इस निष्कर्ष के आधार पर अपास्त कर दिया गया कि वाद विचारणीय नहीं था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम में दीवानी क्षेत्राधिकार पर कोई स्पष्ट रोक नहीं थी। हालांकि, इसने यह माना कि चूंकि अधिनियम की धारा 10 और 11 के साथ-साथ तमिलनाडु संपत्ति (क्षति और हानि की रोकथाम) नियम, 1994 (संक्षेप में "नियम") के नियम 4 में संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने का एक विशिष्ट तरीका निर्दिष्ट किया गया था, इसलिए मुआवजे का दावा करने के अन्य सभी तरीकों को निहितार्थ बाहर कर दिया गया था, और इस प्रकार दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार निहितार्थत वर्जित था। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरी ने तर्क दिया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने सही माना था कि दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है, लेकिन इसने यह मानने में गलती की कि अधिनियम ने निहितार्थतः दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया है—वास्तव में, इसके प्रावधान संकेत देते हैं कि ऐसा क्षेत्राधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपचारों के साथ समवर्ती रूप से मौजूद है।

4.1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सबसे पहले अधिनियम की धारा 7(4) का उल्लेख किया, जो प्रावधान करती है कि धारा 7 के तहत न्यायालय द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे को उसी मामले से संबंधित बाद के दीवानी वाद में मुआवजा देते समय ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 7(4) इस प्रकार दीवानी वाद दायर किए जाने की संभावना को मान्यता देती है, और इस प्रकार मुआवजा देने के लिए दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निहितार्थतः स्वीकार करती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि धारा 7 की

योजना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दं.प्र.सं") की धारा 357 की लगभग शब्दशः प्रतिलिपि है, जो मुआवजे के भुगतान का आदेश देने की आपराधिक न्यायालय की शक्ति से संबंधित है, लेकिन मुआवजे के लिए बाद के दीवानी वाद को दायर करने का भी ध्यान रखती है।

4.2 दूसरे, हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 14 की ओर आकर्षित किया गया, जो अधिनियम के बाहर शुरू की गई कार्यवाहियों को सुरक्षित रखती है, यह तर्क देने के लिए कि दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी धारा 14 के तहत सुरक्षित था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोर दिया कि दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपवर्जन का अनुमान आसानी से नहीं लगाया जाना चाहिए, और उन्होंने इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय **धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 1968 (3) एस.सी.आर. 662 का संदर्भ दिया।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम और नियम एक स्व-निहित कोड हैं और आवश्यक निहितार्थ द्वारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम मुआवजे के निर्धारण और भुगतान के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण बनाते हैं, और इस प्रकार **धुलाभाई** (उपरोक्त) का निर्णय पूरी तरह से लागू होगा, जहाँ यह भी माना गया था कि दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तब अपवर्जित माना जाना चाहिए जब किसी कानून में विशेष रूप से पर्याप्त और संतोषजनक उपचार प्रदान किया गया हो जो सामान्यतः दीवानी न्यायालय की कार्यवाहियों से जुड़ा होता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि मुआवजा देने के लिए दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मान्यता दी गई, तो अधिनियम और नियमों की योजना निरर्थक हो जाएगी।

6. इस बात पर विवाद नहीं है कि अधिनियम के तहत हर्जाने के वाद पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमें केवल यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या दीवानी न्यायालय

का क्षेत्राधिकार आवश्यक निहितार्थ द्वारा वर्जित है। **धुलाभाई** (उपरोक्त) में निर्धारित सिद्धांत इस संबंध में प्रासंगिक हैं। विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों द्वारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपवर्जन के प्रश्न पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि ऐसे अपवर्जन का अनुमान तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी न हो जाएं। हमारे सामने प्रश्न के निर्धारण के उद्देश्य से, हमें केवल **धुलाभाई** (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों का संदर्भ लेने की आवश्यकता है:

"... (1) जहाँ कानून विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को अंतिमता प्रदान करता है, वहाँ व्यवहार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित माना जाना चाहिए यदि वहाँ वह सब करने के लिए पर्याप्त उपचार मौजूद है जो दीवानी न्यायालय सामान्यतः एक वाद में करते हैं। हालाँकि, ऐसा प्रावधान उन मामलों को बाहर नहीं करता है जहाँ विशेष अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है या वैधानिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं किया है।

(2) जहाँ न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर स्पष्ट रोक है, वहाँ प्रदान किए गए उपचारों की पर्याप्तता या संतोषजनकता का पता लगाने के लिए विशेष अधिनियम की योजना की जांच प्रासंगिक हो सकती है लेकिन दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बनाए रखने के लिए निर्णायक नहीं है।

जहाँ कोई स्पष्ट अपवर्जन नहीं है, वहाँ मंशा का पता लगाने के लिए उपचारों और विशेष अधिनियम की योजना की जांच करना आवश्यक हो जाता है और जांच का परिणाम निर्णायक हो सकता है। उत्तरार्द्ध (बाद वाले) मामले में यह देखना आवश्यक है कि क्या कानून एक विशेष अधिकार या दायित्व बनाता है

और अधिकार या दायित्व के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है और आगे यह निर्धारित करता है कि उक्त अधिकार और दायित्व के बारे में सभी प्रश्न इस प्रकार गठित न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और क्या व्यवहार न्यायालयों की कार्यवाहियों से सामान्यतः जुड़े उपचार उक्त कानून द्वारा निर्धारित हैं या नहीं।

X X X

(7) दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपवर्जन का अनुमान तब तक आसानी से नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि ऊपर निर्धारित शर्तें लागू न हों।"

(जोर दिया गया)

6.1 इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या अधिनियम उस कार्य के लिए एक पर्याप्त अंतिम उपचार प्रदान करता है जो दीवानी न्यायालय सामान्यतः एक वाद में करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक हो जाए कि दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपवर्जित कर दिया गया है। अधिनियम और नियमों की योजना की जांच इसी आलोक में की जानी चाहिए।

7. अधिनियम की धारा 1 मुख्य शीर्षक और प्रारंभ से संबंधित है, और धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। महत्वपूर्ण रूप से, उप-धारा (4) "संपत्ति" को किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व वाली, कब्जे वाली या नियंत्रण वाली किसी भी चल या अचल संपत्ति या मशीनरी के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें उप-धारा के खंड (क) से (ज) के तहत सूचीबद्ध संस्थाएं शामिल हैं, उदाहरण के लिए, केंद्र और राज्य सरकार, कोई स्थानीय प्राधिकरण, और कोई भी संस्थान, प्रतिष्ठान या उपक्रम। धारा 3, 4 और 5 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को निर्धारित करती हैं, जबकि धारा 6 जमानत की मंजूरी से संबंधित है।

7.1 धारा 7, जो हमारे विवाद का केंद्र है, पुनरुत्पादन के योग्य है:

"7. मुआवजा देने का आदेश।— (1) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माना की सजा सुनाते समय, न्यायालय निर्णय पारित करते समय आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए पूरे जुर्माने या उसके किसी हिस्से को निम्नलिखित में लगाया जाए—

(क) अभियोजन में उचित रूप से किए गए खर्चों के भुगतान में;

(ख) किसी भी व्यक्ति को अपराध के कारण हुई किसी भी हानि या चोट के मुआवजे के भुगतान में;

(ग) संपत्ति को बदलने या, जैसी भी स्थिति हो, पिछली स्थिति में बहाल करने में, जिसमें कोई भी सड़क, पुल, नौगम्य जलमार्ग, प्राकृतिक या कृत्रिम शामिल है।

(2) यदि जुर्माना ऐसे मामले में लगाया जाता है जो अपील के अधीन है, तो ऐसा कोई भी भुगतान अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अवधि बीतने से पहले, या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है, तो अपील के निर्णय से पहले नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के तहत आदेश एक अपीलीय न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते समय भी दिया जा सकता है।

(4) उसी मामले से संबंधित किसी भी बाद के दीवानी वाद में मुआवजा देते समय, न्यायालय इस धारा के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।

(5) अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा, जब कोई न्यायालय ऐसी सजा देता है जिसमें जुर्माना शामिल नहीं है, तो न्यायालय निर्णय पारित करते समय अभियुक्त व्यक्ति को मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, उस व्यक्ति को जिसने उस कार्य के कारण कोई हानि

या चोट सही है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को सजा सुनाई गई है।"

(जोर दिया गया)

7.2 स्पष्ट रूप से, धारा 7(1) प्रावधान करती है कि जहाँ इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय दोषसिद्धि के बाद जुर्माने की सजा देता है, वह आदेश दे सकता है कि ऐसे जुर्माने को आंशिक या पूर्ण रूप से, अन्य बातों के अलावा, अपराध के कारण हुई किसी भी हानि या चोट के मुआवजे के भुगतान के लिए लगाया जाए, जैसा कि खंड (ख) में उल्लेखित है। साथ ही, उप-धारा (5) प्रावधान करती है कि यदि कोई न्यायालय अधिनियम के तहत केवल कारावास की सजा दे रहा है, तो न्यायालय अभियुक्त को पीड़ित पक्ष को अलग से मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।

7.2.1 इसी चरण में यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि धारा 8 निर्दिष्ट करती है कि अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण मुख्य महानगर दंडाधिकारी या सत्र न्यायालय से नीचे के किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

7.2.2 धारा 7(3) के अनुसार, धारा 7 के तहत एक आदेश, जिसमें उप-धारा (1) और (5) दोनों के तहत आदेश शामिल होंगे, एक अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति के प्रयोग में भी दिया जा सकता है। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण उप-धारा (4) है, जो विशेष रूप से प्रावधान करती है कि उसी मामले से संबंधित बाद के दीवानी वाद में, यदि दीवानी न्यायालय मुआवजा दे रहा है, तो वह अधिनियम की धारा 7 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा।

7.3 आगे बढ़ते हुए, धारा 9 प्रावधान करती है कि अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध किसी राजनीतिक दल या सांप्रदायिक, भाषाई या जातीय समूह द्वारा आयोजित किसी जुलूस, सभा, बैठक, आंदोलन,

प्रदर्शन या किसी अन्य गतिविधि के दौरान किया गया है, वहाँ न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध ऐसे दल या समूह द्वारा भी किया गया है, जो इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान या हानि के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

7.4 धारा 10(1) नुकसान और हानि के मुआवजे के दावों से संबंधित है, जो नुकसान या हानि से प्रभावित व्यक्ति द्वारा, या धारा 2(4) के खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। उप-धारा (2) प्रावधान करती है कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन उसी प्रारूप में होगा जैसा निर्धारित किया जाए।

7.5 धारा 11(1) प्रावधान करती है कि संपत्ति को हुए नुकसान या हानि के मुआवजे के लिए प्रत्येक दावा उस प्राधिकरण को किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जाए। उप-धारा (2) उन कारकों को प्रदान करती है जिन पर मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय निर्धारित प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए, और उप-धारा (3) प्रावधान करती है कि आवेदन का निर्णय करते समय ऐसे प्राधिकरण को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उप-धारा (4) निर्धारित प्राधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी.पी.सी.") में दिए गए न्यायालय की शक्तियां प्रदान करती है ताकि शपथ पर साक्ष्य लिए जा सकें, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं की खोज और प्रस्तुति की जा सके, और अन्य उद्देश्यों के लिए जैसा निर्धारित किया जाए।

7.6 अधिनियम की धारा 12 प्रावधान करती है कि धारा 11 के तहत निर्धारित अधिकारी, मुआवजे की राशि तय करने के बाद, उस राशि का एक प्रमाण पत्र समाहर्ता को जारी कर सकता है, जो उसे भू-राजस्व के बकाया की तरह ही वसूल करेगा। धारा 12-क, धारा 11 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील के तरीके से संबंधित है, जो यह

प्रावधान करती है कि ऐसी अपील उस प्राधिकारी को की जा सकती है जैसा कि निर्धारित किया जाए। उप-धारा (2) विशेष रूप से प्रावधान करती है कि अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी भी कानून के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। धारा 13 राज्य सरकार को अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

7.7 धारा 14 व्यावृत्ति प्रावधान है। चूँकि बहुत कुछ इस प्रावधान के इर्द-गिर्द भी घूमता है, हम इसे नीचे पुनरुत्पादित कर रहे हैं:

"14. व्यावृत्ति — इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में, और इसमें निहित कोई भी बात किसी व्यक्ति को जांच या अन्य कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो इस अधिनियम के अलावा उसके खिलाफ शुरू की जा सकती है।"

7.8 धारा 15, अधिनियम का अंतिम प्रावधान, 'तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (विनाश और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1982' को निरस्त करती है।

8. राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं। नियम 3 यह निर्धारित करता है कि धारा 2(4) के खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाली, कब्जे वाली या नियंत्रण वाली संपत्ति के नुकसान या हानि के लिए कौन और किस तरीके से मुआवजे का दावा कर सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, नियम 4 राजस्व प्रशासन आयुक्त, या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी प्राधिकारी को नियम 3 के तहत किए गए मुआवजे के दावों का निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में निर्धारित करता है। उप-नियम (2) प्रावधान करता है कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या हानि के मुआवजे की राशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी कानून के न्यायालय में इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। उप-नियम (3) सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या हानि के लिए मुआवजा

निर्धारित करते समय विचार किए जाने वाले कुछ अतिरिक्त कारकों को निर्धारित करता है।

8.1 नियम 5 से 10 जांच प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं, जिसमें दोषों का सुधार, लिखित बयान दाखिल करना, पक्षों को नोटिस, समन जारी करना और यदि आवश्यक हो तो कानूनी पेशेवरों की उपस्थिति शामिल है। नियम 11 जांच अधिकारी को क्षतिग्रस्त संपत्ति का निरीक्षण करने की शक्ति देता है, जबकि नियम 12 अधिकारी के समक्ष क्षतिग्रस्त चल संपत्ति को पेश करने की अनुमति देता है। नियम 13 जांच अधिकारी के यात्रा खर्चों से संबंधित है। नियम 14 किसी भी आवश्यक व्यक्ति की संक्षिप्त परीक्षा का प्रावधान करता है। नियम 15 में कहा गया है कि जांच अधिकारी को प्रत्येक गवाह के साक्ष्य के सार का एक ज्ञापन दर्ज करना होगा। नियम 16 प्रावधान करता है कि जांच अधिकारी जांच से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की सहायता ले सकता है। नियम 17 से 19 जांच अधिकारी के लिए तय किए जाने वाले बिंदुओं का अभिलेख तैयार करने, जांच की कार्यवाही की एक संक्षिप्त डायरी रखने, प्रत्येक बिंदु पर अपने निष्कर्षों को संक्षेप में दर्ज करने और ऐसे निष्कर्षों के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता बताते हैं। नियम 20, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता के लागू होने से संबंधित था, उसे जी.ओ. एम.एस. संख्या 1285, गृह (कोर्ट IV), दिनांक 24.10.1994 द्वारा हटा दिया गया था। नियम 21, जो अंतिम नियम है, मुआवजे की वसूली के तरीके से संबंधित है।

9. इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि 1992 में लागू किया गया यह अधिनियम शुरू में केवल सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान और हानि से संबंधित था। अधिनियम को तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (नुकसान और हानि की रोकथाम) अधिनियम, 1994 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसे 09.08.1994 को तमिलनाडु सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, ताकि सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में भी मुआवजा प्रदान किया जा सके। अधिनियम के तहत बनाए गए नियम

09.04.1994 को लागू हुए, यानी अधिनियम के संशोधन से पहले। यद्यपि बाद में नियमों में कुछ संशोधन किए गए जी.ओ. एम.एस. संख्या 1285, दिनांक 24.10.1994 के माध्यम से, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करने में चूक की है, और सार्वजनिक संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति के संबंध में नुकसान के दावे और मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान करने में विफल रही है। उदाहरण के लिए, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, नियम 3, जो मुआवजा मांगने के लिए प्राधिकरण निर्धारित करता है, अभी भी केवल सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में मुआवजे के आवेदनों से संबंधित है। इसी तरह, नियम 4(1), जो उस प्राधिकारी को निर्धारित करता है जिसके समक्ष मुआवजे का दावा किया जाना है, यह स्पष्ट नहीं करता है कि निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए आवेदन किसके समक्ष किया जाना चाहिए। साथ ही, नियम 4(2) में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या हानि के लिए मुआवजे का मूल्यांकन अंतिम होगा, जिसमें निजी संपत्ति के संबंध में नुकसान के भाग्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार, नियम 4(3) सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या हानि के लिए मुआवजे के मूल्यांकन का ध्यान रखता है, और यह इस बात से नहीं निपटता है कि निजी संपत्ति के मामले में नुकसान का मूल्यांकन कैसे किया जाना है। इस प्रकार नियमों को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने संशोधित अधिनियम के अनुरूप बनाने और उसके उचित प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए नियमों को उचित रूप से संशोधित करने में एक चूक की है।

10. हालाँकि, यदि हम यह मान भी लें कि नियम मोटे तौर पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान या हानि के लिए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं, तो भी हमें अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क में बल मिलता है कि अधिनियम की योजना दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने की परिकल्पना नहीं करती है।

11. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियमों को शाब्दिक नहीं बल्कि व्यापक रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम, नियमों के साथ मिलकर, दो तरह से मुआवजे का प्रावधान करता है। पहला, यह अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के मुकदमे के अंत में दिया जा सकता है, या अभियुक्त पर लगाए गए जुर्माने में से भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है। यह दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत मुआवजा देने की आपराधिक न्यायालय की शक्ति के समान है। दूसरा, नियमों के तहत परिकल्पित संक्षिप्त जांच के बाद, धारा 10 के तहत परिकल्पित आवेदन पर मुआवजा दिया जा सकता है। यह कुछ हद तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संक्षेप में "1986 अधिनियम") के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए परिकल्पित संक्षिप्त प्रक्रिया के समान है। यह इंगित करेगा कि अधिनियम और नियम संपत्ति के नुकसान और हानि के मुआवजे का दावा करने के लिए एक विशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। इसी आधार पर उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि दीवानी न्यायालय को हर्जाने के वाद का निर्णय करने के लिए समवर्ती क्षेत्राधिकार वाला नहीं कहा जा सकता।

12. हालाँकि, ऐसा तर्क खारिज किए जाने योग्य है। हम सबसे पहले अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के मुकदमे के बाद धारा 7 के तहत आपराधिक न्यायालय द्वारा मुआवजा देने या उसके प्रावधान के पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रावधान स्पष्ट रूप से उसी मामले से संबंधित अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही के बाद शुरू किए गए दीवानी वाद की संभावना को मान्यता देता है, जहाँ यदि दीवानी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय मुआवजा दे रहा है, तो उसे अधिनियम की धारा 7 के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह तर्कसंगत नहीं है कि अधिनियम दीवानी न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार को वर्जित करते हुए बाद में दीवानी वाद दायर करने की अनुमति देगा।

13. इसके अलावा, नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 10 के तहत परिकल्पित मुआवजा मांगने का संक्षिप्त उपचार भी हर्जाने के लिए वाद दायर करने से नहीं रोकता है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 14 महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि अधिनियम उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त है, न कि उसके अल्पीकरण में। यह आगे आदेश देता है कि अधिनियम में निहित कोई भी बात किसी व्यक्ति को जांच या अन्यथा किसी ऐसी कार्यवाही से छूट नहीं देगी जो अधिनियम के अलावा उसके खिलाफ शुरू की जा सकती है। लागू "कानून" में सामान्य कानून शामिल होगा, जिसके तहत हर्जाने के अपकृत्य उपचार का दावा किया जा सकता है, जिसका पीछा केवल दीवानी न्यायालय में ही किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम, धारा 14 के माध्यम से, हर्जाने के वाद पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।

14. इस संबंध में, 1986 अधिनियम की धारा 3 का संदर्भ लेना उपयोगी होगा, जो अधिनियम की धारा 14 के समान है, और यह प्रावधान करती है कि 1986 अधिनियम लागू अन्य कानूनों के अतिरिक्त है न कि उनके अल्पीकरण में:

"3. अधिनियम किसी अन्य कानून के अल्पीकरण में नहीं।— इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।"

14.1 इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर इस प्रावधान पर विचार किया गया है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि उपभोक्ता मंचों के समक्ष उपलब्ध उपचार किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध कई समवर्ती उपचारों में से केवल एक हो सकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में, इस न्यायालय ने *पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारत संघ* (डब्ल्यू.पी. (सी.) संख्या 43/2019, दिनांक 09.08.2019 को तय) में यह टिप्पणी की कि

विभिन्न कानूनों जैसे 1986 अधिनियम, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत फ्लैट आवंटियों को मिलने वाले उपचार समवर्ती हैं। हालांकि, हमारे उद्देश्यों के लिए, हम दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर 1986 अधिनियम की धारा 3 के प्रभाव की जांच करने तक खुद को सीमित रख सकते हैं। *कर्नाटक राज्य बनाम विश्वभारती हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, (2003) 2 एस.सी.सी. 412* में की गई निम्नलिखित चर्चा हमारे लिए पर्याप्त है, जहाँ इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1986 अधिनियम दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को प्रतिस्थापित नहीं करता है:

"46. अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के कारण, यह स्पष्ट है कि इसके तहत प्रदान किए गए उपचार अन्य कानूनों के तहत प्रदान किए गए उपचारों के अल्पीकरण में नहीं हैं। उक्त अधिनियम सिविल न्यायालयों या अन्य वैधानिक अधिकारियों के क्षेत्राधिकार का पूरक है, न कि उनका प्रतिस्थापन ।

X X X

53. ... इसके अलावा, मुख्य रूप से मंचों/आयोगों का क्षेत्राधिकार हर्जाना प्रदान करना है। यदि किसी शिकायतकर्ता को लगता है कि उसे दीवानी न्यायालय में बेहतर और प्रभावी उपचार मिलेगा क्योंकि उसे व्यादेश के आदेश की मांग करनी पड़ सकती है, तो वह निर्विवाद रूप से एक उपयुक्त दीवानी न्यायालय में वाद दायर कर सकता है या अन्य कानूनों में प्रदान किए गए कुछ अन्य उपचारों का सहारा ले सकता है।"

(जोर दिया गया)

14.2 हम इस न्यायालय द्वारा अपने पिछले निर्णय *इंडियन मेडिकल*

एसोसिएशन बनाम वी.पी. शांता, (1995) 6 एस.सी.सी. 651 में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का भी संदर्भ ले सकते हैं, जहाँ चिकित्सा लापरवाही के माध्यम से सेवा में कमी के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए उपभोक्ता मंचों को सक्षम मानते हुए, निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी:

"37. ... विशेषज्ञों के साक्ष्य दर्ज करने की आवश्यकता वाले जटिल मुद्दों वाली शिकायतों में, शिकायतकर्ता को उचित राहत के लिए दीवानी न्यायालय जाने के लिए कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 3, जो यह निर्धारित करती है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे, उपभोक्ता के आवश्यक राहत के लिए दीवानी न्यायालय जाने के अधिकार को सुरक्षित रखती है..."

(जोर दिया गया)

14.3 हमारे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान अधिनियम के संबंध में भी इसी तरह का सिद्धांत लागू होता है। अधिनियम की धारा 14, जो लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अतिरिक्त है न कि उनके अल्पीकरण में, एक पीड़ित व्यक्ति को यदि वह ऐसा चाहता है, तो अधिनियम की धारा 10 के तहत परिकल्पित उपचार का लाभ उठाने के बजाय राहत के लिए दीवानी न्यायालय जाने की अनुमति देती है। स्पष्ट रूप से, अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा केवल एक अतिरिक्त उपचार की प्रकृति का है जिसे उसी राहत के लिए सिविल वाद दायर करने के स्थान पर अपनाया जा सकता है।

15. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि चूंकि धारा 10 के तहत मुआवजे का दावा

केवल संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से ही निर्धारित किया जा सकता है, इसलिए यह उन उपचारों के पूर्ण विकल्प के रूप में नहीं है जिन्हें दीवानी न्यायालय में अपनाया जा सकता है और एक पूर्ण मुकदमे के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है, भले ही अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे का निर्धारण करने वाले निर्धारित प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हों।

16. अधिनियम और नियमों की संपूर्ण योजना के मूल्यांकन पर, और **धुलाभाई** (उपरोक्त) द्वारा निर्धारित परीक्षणों को देखते हुए, हम इस सुविचारित राय के हैं कि यह अधिनियम सामान्य कानून के तहत हर्जाने के दावे का स्थान नहीं लेता है और न ही उसे रोकता है, जो किसी दीवानी वाद में दीवानी न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए आ सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह अधिनियम न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ द्वारा दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करता है, और उच्च न्यायालय ने यह मानकर कि अपीलकर्ता द्वारा दायर वाद विचारणीय नहीं था, यहाँ के उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की है।

17. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि वाद विचारणीय है, गुण-दोष के आधार पर वाद को डिक्री करने की कार्यवाही की थी। उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत दायर अपील का निर्णय केवल वाद की विचारणीयता से संबंधित प्रारंभिक बिंदु पर किया गया था। हमारे इस निष्कर्ष के आलोक में कि वाद विचारणीय है, मामले को गुण-दोष के आधार पर प्रथम अपील की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाना आवश्यक है।

18. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है, और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय

के निर्णय को अपास्त कर दिया जाता है। मामले को गुण-दोष के आधार पर प्रथम अपील, यानी 2018 की ए.एस. (एम.डी.) संख्या 143, का निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।